(b) Distance method-covering all States	5
3. *Performance of which:*	7.5
(a) Tax effort	2.5
(b) Fiscal Management	2.0
(c) *National Objectives*	3.0
(1) Population control	1.0
(2) Elimination of Female illiteracy	1.0
(3) On-time completion of externally aided projects	0.5
(4) Success in land reforms	0.5
4. Special Problems	7.5

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4111. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य तथा स्वरूप क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में सीमा कार्यक्रमों को जिन विशिष्ट स्थानों में कार्यान्वित किया जाना है, उनका गुजरात समेत राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती, अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह कार्यक्रम उन राज्यों तक विस्तारित है जिनकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा लगती है अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। बहरहाल, गुजरात सहित इन राज्यों में सीमा क्षेत्रों में विकास के लिए ध्यान केन्द्रित करने हेतु इस कार्यक्रम के तहत स्कीमों को केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगने वाले ब्लॉकों में शुरू किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य में शुरू की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के विषय में निर्णय राज्य स्तरीय छानबीन समितियों द्वारा किये जाते हैं। उत्तर-पश्चिमी राज्यों अर्थात् राजस्थान और गुजरात में शुरू की गई स्कीमें संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सुरक्षा आदि से सम्बद्ध हैं। केन्द्रीय बजट 1998-99 में किए गए प्रावधान के आधार पर चालू वर्ष अर्थात 1998-99 में उत्तर-पश्चिमी राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गये आबंटन इस प्रकार हैं:-

राज्य	(रु करोड़) आवंटन
राजस्थान	26.52
गुजरात	8.88

योजना आयोग के पास संगृहीत राशि

4112. **श्री अखिलेश दास:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक योजना आयोग के पास संगृहीत राशि कितनी थी;

(ख) क्या योजना आयोग को नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उन संसाधनों के बारे में, जो कि उसके पास उपलब्ध हैं और जिनकी कमी पड़ जाने की संभावना है, कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) योजना के लिए परिकल्पित समस्त वित्तीय संसाधन विभिन्न क्षेत्रकों और योजना में शामिल कार्यक्रमों के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। योजना कार्यक्रमों के लिए बजट-आबंटन, उपलब्ध संसाधनों और क्षेत्रकों की प्राथमिकताओं के आधार पर, संबंधित वर्षों के बजटों में प्रत्येक वार्षिक योजना के लिए किए जाते हैं। किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि बाद में व्यपगत हो जाती है और इसलिए वित्तीय संसाधनों के संगृहीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में, नौवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों

की आवश्यकता 1996-97 मूल्यों पर 8,75,000 करोड़ रु० आंकी गई है। तथापि, सरकार ने प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंण्डा में यथावर्णित परिवर्तित प्राथमिकताओं को उसमें दर्शाया जा सके। अपेक्षित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों सहित विस्तृत कार्य योजनाएं पहले ही तैयार की जा रही हैं, जिन्हें, अंतिम रूप देकर वर्तमान प्रारूप के साथ समेकित कर दिया जाएगा।

Share of Various Sectors in GDP and National Export

4113. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the share of Industry, Animal Husbandry, Agriculture, Sericulture and Fisheries in the G.D.P. and national export during the last five years, year-wise; and

(b) the plan and non-plan budgetary allocations made against each sector during Eight Plan and proposed for Ninth Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAY AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) The share of Industry, Agriculture including Livestock and Fishing as percentage of Gross Domestic Product (GDP) as estimated by the Central Statistical Organisation (CSO) for the last five years is given in Annexure. [*See Appendix 184, Annexure No. 101*]. Estimates of GDP from Sericulture is not prepared by CSO seperately. The share of Industry, Amimal Husbandry, Agriculture and Sericulture in National export for the last five years is given in Annexure. [*See Appendix 184, Annexure No.101*]

(b) The Plan outlay headwise, for the Eighth Five Year Plan is given in Annexure. [*See Appexdix 184, Annexure No. 101*]. The non-plan allocations, headwise, for the Eighth Five Year Plan is given in Annexure. [*See Appendix 184, Annexure No. 101*] For the Ninth Five Year Plan, the Draft Plan, approved at the internal meetings of the Planning Comission was released by Deputy Chairman, Planning Commission. This Plan is yet to be considered by the National Development Council. The Government has decided to review this Draft so as to suitably reflect the altered priorities, as enunciated in the National Agenda for Governance. Detailed action plans are already under preparation whcih will, upon finalisation be integrated with the existing draft. This review document will then be submitted through due process, for consideration and approval of the National Development Council.

केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन

4114. **श्री ओंकर सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रतिवर्ष राज्यवार मूल्यांकन किया जाता है, यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों की कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्या स्थिति रहीं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति रहीं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) इस विभाग द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की कुछ योजनाएं मासिक आधार पर प्रबोधित की जाती है। बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति के संदर्भ में श्रेणीवार निर्धारण का कार्य राज्यों/क्षेत्रों को सौंपा गया है। बीस सूत्री कार्यान्वयन के प्रबोधन के आधार पर वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों का श्रेणीवार निर्धारण संलग्न विवरण में दिया गया है नीचे देखिए सन् 1996-97 में राजस्थान तृतीय एवं 1997-98 में प्रथम रहा।

विवरण

वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के निष्पादन पर राज्यों का श्रेणी वार निर्धारण

क्रम सं०	राज्य/संघ-क्षेत्र	1996-97	1997-98
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	9	15